भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2271
दिनांक 20 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय:- कृषि में इजरायली तकनीक

2271. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेती में न्यूनतम भूमि, न्यूनतम लागत और कम पानी में अधिक उपज प्राप्त करने की इजरायली तकनीक का प्रयोग हरियाणा के करनाल जिले में शुरू हो गया है;
(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रौद्योगिकी के परिणामों, जैसे उपज, फसलों की गुणवत्ता आदि के संबंध में अध्ययन किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का उक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत भारत-इस्राइल कार्य योजना के माध्यम से 29 फसल विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) अनुमोदित किए गए हैं और हरियाणा के करनाल जिले में सब्जी के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र सहित माशाव, इज़राइल की तकनीकी सहायता से पूरे किए गए हैं। किसानों ने अधिक उपज, न्यूनतम लागत और कम पानी प्राप्त करने के लिए हरियाणा सहित देश भर के किसानों द्वारा पॉली हाउस एवं नेट हाउस, प्लास्टिक लो टनल एवं मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि जैसी संरक्षित संरचनाओं सहित इस्राइली प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाया है।

(ख): राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, राज्यों द्वारा साझा किए गए व्यावहारिक अनुभव से इन तकनीकों को अपनाने पर उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता को दर्शाता है।

(ग): जल संरक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए आधुनिक उत्पादन तकनीकों का प्रदर्शन, अन्य बातों के साथ-साथ, इन सीओई के कुछ प्रमुख हस्तक्षेप हैं। इन केंद्रों में बागवानी के विकास के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन केंद्रों में लगभग 3.4 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है।

****